पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 20, अंक 3/2019

भारतीय सेना और परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा के लिए मिलकर कार्य करेंगे

'भारतीय सेना सड़कों के सबसे बड़े उपयोग करने वालों में से एक है। इसी वजह से सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर गहराई से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना और राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर साथ मिलकर कार्य कर सकती है।'

भारतीय सेना के दक्षिण–पश्चिम कमान के कमांडर लेफ्टीनेंट जनरल चेरिश मैथसन ने यह विचार 'कट्स' इंटरनेशनल के तत्वावधान में एवं सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से जयपुर में आयोजित 'गुड सेमेरिटन गाईड लाइन–चेलेंजेज एण्ड वे फॉरवर्ड' विषयक राज्य स्तरीय सेमिनार में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सेना में शारीरिक रूप से चोट लगना या क्षति सर्विस का हिस्सा है, लेकिन वे सर्विस के बाहर हुई किसी भी दुर्घटना को गंभीरता से लेते हैं।

पिछले पांच वर्षों में एस.ई.कमांड में 130 से अधिक व्यक्ति सेना सर्विस के बाहर सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। उन्होंने 'गुड सेमेरिटन' शब्द को हिन्दी शब्दावली में अच्छा शब्द खोजने पर जोर दिया। जिससे आम व्यक्तियों को इसका मतलब अच्छी तरह से समझ आ सके।

इससे पूर्व 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने 'गुड सेमेरिटन' को परिभाषित करते हुए सेना और सड़क सुरक्षा के बीच के संबंध के

बारे में संक्षेप में बताया और कहा कि पिछले दशक के दौरान कुल 13 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई। वर्ष 2018 में कुल 4 लाख 16 हजार 968 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हुई है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की उच्चतम दर देखी गई है। उन्होंने 'गुड सेमेरिटन' के अर्थ को परिभाषित करते हुए बताया कि जो व्यक्ति किसी भी पुरस्कार की उम्मीद किए बिना सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करता है उसे एक अच्छा मददगार कहा जाता है।

कार्यक्रम में राजेश कुमार यादव, परिवहन आयुक्त ने राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए विभाग की ओर से किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की प्रभावी भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सी.एस.ओ. सहित सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों के कारण पिछले तीन सालों में दुर्घटनाओं और दुर्घटना से होने वाली मौतों में कमी आई है। लेकिन इसमें अभी भी और सुधार की जरूरत है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेकर इस मुद्दे पर कार्य करने की योजना बना रहा है।

सेमिनार में दीपक कुमार, डी.आईजी (ट्रैफिक पुलिस) मुख्यालय जयपुर ने कहा कि 'गुड सेमेरिटन गाईड लाइन्स' बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका सभी को पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस तथ्य पर खास जोर देते हुए कहा कि घायलों की मदद के लिए लोगों की पहल महत्वपूर्ण है और व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।

तकनीकी सत्र में डॉ. डी.एस.मीणा, अधीक्षक, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर; डॉ. वीरेन्द्र राठौड़, डी.टी.ओ., परिवहन विभाग; डॉ. एल.एन. पांडे, सदस्य, सड़क सुरक्षा सेल, परिवहन विभाग; श्री पाल, इंस्पेक्टर, ट्राफिक पुलिस, जयपुर एवं मधु सूदन शर्मा, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, 'कट्स' ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा एवं 'गुड सेमेरिटन' से संबंधित विभिन्न जानकारियां देकर लाभान्वित किया। दीपक सक्सेना, सहायक निदेशक, 'कट्स' ने तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की और 'गुड सेमेरिटन' की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। सेमिनार में संबंधित विभागों के अधिकारियों, शैक्षिक संस्थाओं और मिडिया प्रतिनिधियों सहित करीब 85 प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

इस अंक में...

- भामाशाह योजना में फर्जी क्लेम 3
- जबरन रिटायर किए जाएंगे भ्रष्ट अफसर 5
- बिल में करंट दौड़ाने की टैरिफ याचिका दायर . 8
- जल संकट की चपेट में भारत 9
- फैमिली प्लानिंग का जिम्मा महिलाओं पर? . 10

'ग्रीन एक्शन वीक' - 2019 के तहत ई-वेस्ट पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

'कट्स' द्वारा 'स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन' के सहयोग से प्रत्येक वर्ष सितम्बर एवं अक्टूबर माह के दौरान राजस्थान में 'ग्रीन एक्शन वीक' नामक अभियान संचालित किया जाता है। अभियान के तहत इस वर्ष का विषय 'शेयरिंग कम्यूनिटी' रखा गया है।

इस अभियान का उद्देश्य आमजन में सामुदायिक सहभागिता की भावना जागृत करना है। अभियान के तहत 'कट्स' द्वारा जयपुर शहर में उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिनमें किचन गार्डन विकसित करना, ई-वेस्ट का संग्रहण, साझा की दीवार, स्कूल मीटिंग, सामुदायिक बैठकें, नुक्कड़ नाटक, हस्ताक्षर अभियान जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त गतिविधियों के क्रम में 30 सितम्बर को जयपुर स्थित 'कट्स' कार्यालय में ई-वेस्ट संग्रहण पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि ई-वेस्ट आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही, इससे मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि ई-वेस्ट से भारत के शहरों में बड़े-बड़े भंडार स्थापित हो रहे हैं। भारत ई-वेस्ट के मामले में यू.एस.ए., चीन, जापान और यू.के. के बाद पांचवें स्थान पर है। कुल ई-वेस्ट का मात्र 0.6 प्रतिशत ही सही मायने में निस्तारित हो पाता है। ई-वेस्ट के निस्तारण एवं उचित प्रबंधन की आवश्यकता है।

कार्यशाला में 'ईटको ई-वेस्ट रिसाइक्लिर प्रा. लि.' के प्रतिनिधि करण सिंह एवं बलराम सिंह ने ई-वेस्ट के प्रबंधन की गतिविधियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी ई-वेस्ट एवं अन्य इलेक्ट्रिकल आईटम कबाड़ी को नहीं बेंचे, बल्कि इन्हें ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर पर जमा कराएं।

इस अभियान के तहत 'ईटको ई-वेस्ट रिसाइक्लिर प्रा. लि.' द्वारा जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 'ई-वेस्ट' बिन 'कट्स' के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे। कार्यशाला में इस विषय पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिया प्रशिक्षण

'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन, स्वीडन के सहयोग से संचालित प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के तहत 29 सितम्बर को प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय कृषक आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आर.के.डामोर ने जैविक खेती के महत्व और आवश्यकता पर जानकारी देते हुए कहा कि आज रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं से युक्त कृषि उत्पादनों के सेवन से लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने जैव तकनीक द्वारा कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसान जैविक छिड़काव तैयार कर कीट प्रबंधन कर सकते हैं।

कार्यशाला में 'कट्स' जयपुर के कार्यक्रम अधिकारी राजदीप पारीक ने बताया कि 'कट्स' द्वारा राजस्थान के दस जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना संचालित की जा रही है। जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला के माध्यम से किसानों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, ताकि वे अपने खेत पर जैविक उत्पादन कर ज्यादा लाभ ले सकें।

'कट्स' मानव विकास केंद्र के उप केंद्र समन्वयक मदन गिरी गोस्वामी ने परियोजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'कट्स' द्वारा ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बैठकें, जैविक सीड्स सेल, स्कूलों में जैविक गार्डन का विकास एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण एवं किसान शैक्षणिक भ्रमण आदि का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जैविक कृषि जागरूकता अभियान के भंवर सिंह पीलीबंगा, जैविक किसान गोपाल साहू, बंशीलाल धाकड़, जमनालाल गुर्जर व एडवोकेट नरेन्द्र कुमार शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के आरंभ में 'कट्स' के केंद्र समन्वयक गौहर महमूद ने किसानों को दिए जाने वाले जैविक खेती प्रशिक्षण में सक्रियता से भाग लेने का आग्रह किया।

कार्यशाला में किसानों को जैविक खेती पर आधारित पेम्पलेट्स वितरित किए गए और जैविक खेती से संबंधित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। प्रतापगढ़ जिले की सभी पंचायत समितियों के 76 किसानों ने कार्यशाला में सक्रियता से भाग लिया। अगले दिन कृषि विज्ञान केंद्र, बांसवाड़ा पर किसानों को भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉ. गोपाल कोठारी ने वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी दी तथा केंद्र की गतिविधियों से किसानों को रूबरू करवाया।

मनमर्जी से मंजूर कर दिए 900 करोड़

गांवों में शहरों की सुविधाएं विकसित करने के मकसद से चल रहे केंद्र सरकार के श्यामा प्रसाद रुबन मुखर्जी मिशन योजना में बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। योजना के तहत राजस्थान में विकसित किए जा रहे दो चरणों में 10 क्लस्टरों के लिए राज्य की सरकारी मशीनरी ने नियमों के विपरीत जाकर करीब 900 करोड़ रुपए की विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) मंजूर कर दी। जबकि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार राज्य के पास ये डीपीआर मंजूर करने की शक्तियां ही नहीं थीं।

छह माह बाद जब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आईएएस अधिकारियों की समिति की यह चूक पकड़ी गई तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिलों में बड़ी संख्या में स्वीकृत कार्यों को रोकने का फरमान संबंधित कलक्टरों को भिजवाया गया। *(रा.प., 08.08.19)*

कमीशन के चक्कर में खरीदी मशीनें

तीन साल में 35 करोड़ की लागत से बनने वाले गोविंदगढ़ सरस प्लांट को राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लि. (आरसीडीएफ) के अधिकारी छह साल में भी नहीं बना पाए। अधिकारियों ने सिविल वर्क पर जोर देने की अपेक्षा मशीन खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। यहां तक कि अधिकारियों ने सिविल वर्क पूरा होने से पहले ही कमीशन के चक्कर में करोड़ों रुपए की मशीनें खरीद ली, जो अब कबाड़ हो गई हैं।

इन मशीनों का वारंटी पीरियड भी निकल गया है। अब अधिकारियों को मशीनों का मेंटीनेंस आरसीडीएफ के खर्च पर कराना होगा। जिसमें लाखों रुपए खर्च करने होंगे। प्लांट की स्वीकृति वर्ष 2011-12 में हुई थी। गोविंदगढ़ प्लांट की क्षमता मात्र 3 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन पाउडर बनाने की है। यह प्लांट 6 लाख लीटर दूध क्षमता का बनता तो ज्यादा फायदेमंद होता। *(दै.भा., 02.09.19)*

खातों में ही रह गया विकास का पैसा

प्रदेश में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को दी जाने वाली ग्रांट का पूरा पैसा खर्च ही नहीं हुआ। स्थानीय निकायों में पिछले वर्ष जमा 1652 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो सके। वहीं जिला परिषदों में 1872 करोड़ रुपए और पंचायत समितियों में करीब 1450 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए।

प्रदेश के दौरे पर आए 15वें वित्त आयोग की ओर से अर्थशास्त्रियों, उपभोक्ता संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह स्थिति सामने आई। विकास कार्यों पर खर्च होने वाली इस राशि का उपयोग नहीं होने पर वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और आयोग के सदस्यों ने चिंता जताई है। *(दै.भा., 09.09.19)*

भामाशाह योजना में फर्जी क्लेम

प्रदेश में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना पर सरकार सालाना 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करती आ रही है। योजना में अधिक से अधिक मरीजों को लाभ मिले, इस उद्देश्य से योजना पर पिछली सरकार का खास फोकस रहा है। लेकिन कुछ निजी अस्पताल योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा कर चांदी कूटने का काम कर रहे हैं।

भाजपा सरकार के समय शुरू हुई इस योजना में पहले भी फर्जी क्लेम उठाए जा चुके हैं। जांच के बाद कई अस्पतालों को प्रतिबंधित व योजना से बाहर करने की कार्रवाई भी हुई। अब फिर कई मामले ऐसे आए हैं जिनमें कुछ निजी अस्पताल गरीब मरीजों को अंधेरे में रख कर बिना जरूरत धड़ाधड़ ऑपरेशन कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल ही जयपुर, अजमेर और सीकर में निजी अस्पतालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें फर्जी क्लेम कर मरीजों के कार्ड पर मोटी कमाई की गई। *(रा.प., 22.07.19)*

शौचालय बनाने में प्रदेश फिसड्डी

ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श शौचालय बनाने के मामले में प्रदेश के 13 जिले फिसड्डी साबित हुए है। प्रदेश की राजधानी सहित कई जिलों में अभी तक कोई प्रगति नहीं होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नाराजगी जताई है। इस मामले में विभाग के मंत्री सचिन पायलट पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 50 हजार रुपए की लागत से आदर्श शौचालय बनाये जाने हैं। राज्य की शौचालय निर्माण की औसत प्रगति मात्र 10.51 प्रतिशत है। अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर ऐसे जिले हैं, जहां अभी तक इस दिशा में कोई काम ही शुरू नहीं हुआ। *(दै.न., 02.08.19)*

कब्र से आकर मुर्दे करते हैं मजदूरी

जैसलमेर जिले की मानासर ग्राम पंचायत जहां पर केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने के चक्कर में पंचायत ने मुर्दों को भी रोजगार की गारंटी दे दी है। योजना के तहत ग्राम पंचायत में मजदूरों की सूची में रणजीता राम, नखता राम जैसे दर्जनों नाम ऐसे हैं जो सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं।

लेकिन उनके नाम से सरकारी कागजों में मजदूरी करना दिखाया जा रहा है और इसका भुगतान भी नियमित रूप से उठ रहा है। दिलचस्प यह है कि इनका मृत्यु प्रमाण-पत्र खुद पंचायत ने जारी किया है। *(दै.न., 13.08.19)*

राजनीति में फंसा वर्षा जल संचय

प्रदेश में इस बार जमकर बरसा चौमासा, अब जाने को है, लेकिन इस पानी को बचाने के सरकारी अभियान राजनीति की करवट में दब कर नकारा ही साबित हुए। पिछले साल दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित होने के बावजूद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने आनन-फानन में अक्टूबर माह में जल स्वावलंबन अभियान का चौथा चरण शुरू कर दिया।

दिसंबर में जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस शासन आया तो इस अभियान पर अघोषित रोक लगा दी गई। नतीजा यह निकला कि ना तो जल स्वावलंबन में स्वीकृत काम पूरे हो पाए, ना ही कांग्रेस की नई योजना जमीन पर उतर पाई। *(रा.प., 21.09.19)*

हर सरकार में बंटी सब्सिडी की रेवड़ियां

वोट के लालच में सरकारें विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी की रेवड़ियां बांटती गई, जिसका नतीजा लाखों आम उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल चुका कर उठाना पड़ रहा है। अभी कृषि और बीपीएल उपभोक्ताओं को बिल में सालाना 11 हजार 500 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है।

सरकार ने सब्सिडी तो दे दी, लेकिन अब तक करीब 11 हजार करोड़ रुपए डिस्कॉम को दिए ही नहीं। इनमें बॉन्ड राशि भी शामिल है। डिस्कॉम ने भी इस बकाया राशि को घाटा मानते हुए टैरिफ बढ़ाने के लिए याचिका में शामिल कर लिया है। इस तरह सब्सिडी से हुए घाटे को दिखाकर टैरिफ में दर बढ़ाने का खेल चल रहा है। सालाना 1800 करोड़ यूनिट बिजली छीजत-चोरी का बिल भी आम जन के सिर पर लादा जा रहा है।

मामला राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास है। माना जा रहा है कि फैसला कुछ भी हो, बिजली दर बढ़ाने में इस बकाया राशि को शामिल करना तय है। *(रा.प., 04.08.19)*

फर्जी महिला समूहों को दे दिया ऋण

अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कॉरपोरेशन की लोन स्कीम में प्रदेश के 42 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा फर्जी तरीके से लोन उठाने का मामला सामने आया है। ताज्जुब की बात यह है कि घोटाले का खुलासा चार साल बाद तब हुआ जब किश्त नहीं चुकाने पर जिला प्रोग्राम अधिकारी इनके लोन लेने के दौरान दिए गए पते पर पहुंचा तो सभी महिला स्वयं सहायता समूहों के पते फर्जी निकले।

विभाग ने 2012 से 2015 तक 42 स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ 22 लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया। यह लोन रोजगार के लिए 7 फीसदी ब्याज दर पर दिया जाता है। ताज्जुब की बात है कि लोन वितरण करने वाले तत्कालीन अधिकारियों ने इन समूहों के आवेदनों का वेरिफिकेशन तक नहीं किया। *(दै.भा., 31.07.19)*

कर्मचारियों ने बनवा लिए बीपीएल कार्ड

जिन पर सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए नियमों की पालना करवाने का जिम्मा है, वे अब खुद गलत तरीकों से लाभ उठाने लगे हैं। मामला भवानी मंडी नगरपालिका से जुड़ा है, जहां नगरपालिका के 17 कर्मियों ने निर्धन व्यक्तियों के लिए लागू की गई बीपीएल योजना में परिवार के लिए राशन कार्ड बनवा रखे हैं। ये परिवार अपात्र होते हुए भी कई सालों से इसका लाभ ले रहे हैं।

जब इसकी भनक एसडीएम राजेश डागा को लगी तो एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि पालिका के 17 कर्मचारियों के राशन कार्ड अपात्र होते हुए भी बीपीएल के बने हुए हैं। उन्होंने आदेश जारी कर पालिका के इन सभी 17 कर्मियों के बीपीएल राशन कार्ड खारिज करने के आदेश दिए। *(रा.प. एवं दै.भा., 22-.08.19)*

नहीं बना सतत विकास का विजन दस्तावेज

लोगों के जीवन में खुशहाली और संपन्नता लाने और उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय सतत विकास लक्ष्यों के प्रभाव में आने के चार साल बाद भी देश में इसके लिए न तो विजन दस्तावेज तैयार हो पाया है और न ही पैसे की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों की सहमति से सतत विकास लक्ष्य 2015 में तय किए थे, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है।

संसद में पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने केंद्र और राज्य के स्तर पर कई कदम उठाए हैं। हर क्षेत्र में कई ऐसे पहलु हैं जिन पर ध्यान देने के साथ ही सुधारात्मक उपायों की जरुरत है। नीतिगत दस्तावेज तैयार करने का काम अब भी पूरा नहीं हो सका है। रोडमैप तैयार करने का काम अभी बाकी है। कैग का कहना है कि लक्ष्यों को हासिल करने एवं संसाधन जुटाने के लिए धनराशि की जरूरत का आकलन अभी तक नहीं किया गया है। *(दै.न., 15.07.19)*

शहर पर हावी नगर निगम की लापरवाही

जयपुर शहर में बने ऐतिहासिक परकोटे की ख्याति और इसमें बसे प्राचीन शहर ने यूनेस्को तक जयपुर का नाम रोशन कर दिया। इसके बावजूद संरक्षित परकोटे की दीवार अतिक्रमण के चलते कई जगह से गुम हो चुकी है। गुम हो चुकी परकोटे की दीवार का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो इसकी खोई आभा वापस लौटाने को कहा गया। निर्देश मिले कि पुरातत्व विभाग इसके लिए नगर निगम को पैसा देगा।

आदेश की पालना में 2015 में पुरातत्व विभाग ने 12 करोड़ 67 लाख रुपए और दो दिन बाद 9 जुलाई 2015 को 18 करोड़ रुपए नगर निगम के खाते में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते नगर निगम को मिली इस राशि से तीन साल बीतने पर भी संरक्षित घोषित दीवारों को संरक्षण नहीं मिला। *(दै.भा., 20.09.19)*

जीएसटी क्रियान्वयन पर उठा सवाल

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर उंगलिया उठाई है। कैग ने कहा है कि जीएसटी को लेकर दखलंदाजी रहित जिस ई-टैक्स प्रणाली की कल्पना की गई थी, वह अब तक भी साकार नहीं हुई है। दो साल बाद भी बिलों के मिलान (इनवॉयस मैचिंग) के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कैग ने यह टिप्पणी जीएसटी पर उसकी पहली ऑडिट रिपोर्ट में की है। लोकसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है जीसटी की रिटर्न प्रणाली की जटिलता और तकनीकी दिक्कतों के चलते इनवॉयस मैचिंग के नियम को वापस लेने के कारण जीएसटी प्रणाली में इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी होने का खतरा मंडराने लगा है। *(रा.प., 01.08.19)*

जबरन रिटायर किए जाएंगे भ्रष्ट अफसर

राजस्व विभाग के 27 'भ्रष्ट एवं नकारा' वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट से शुरू हुआ सफाई अभियान अब केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में शुरू कर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को हर महीने अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन कर दागी व नकारा कर्मचारियों की सूची बनाने का आदेश दिया है।

ऐसे कर्मियों को मौलिक नियमों के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस कवायद में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और बैंकों को शामिल किया गया है। सूची हर महीने की 15 तारीख तक जमा करानी होगी। यह व्यवस्था इसी माह से लागू कर दी गई है। *(रा.प., 03.07.19)*

भ्रष्टाचार में 'डूबे' अफसरों को किया सेवानिवृत्त

केंद्र सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के 27 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। इनमें सबसे ज्यादा 11 अफसर भोपाल के हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार व रिश्वत लेने जैसे आरोप हैं।

जानकारी के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति में सुपरिटेंडेंट और एओ रैंक के अधिकारी हैं। भोपाल, नागपुर, बेंगलूरू, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मेरठ, मुंबई, बेंगलूरू कस्टम, मुंबई कस्टम जोन-2 और चंडीगढ़ जोन के अधिकारियों को बाहर करने के लिए फंडामेंटल रूल 56(जे) अपनाया गया है। जून में सीबीआइसी के भ्रष्ट-नकारा 15 वरिष्ठ अफसरों पर जबरन रिटायरमेंट एक्शन के बाद 27 अन्य राजस्व अफसर रिटायर किए गए, इनमें सीबीआइसी के 12 अधिकारी थे। *(रा.प., 27.08.19)*

दूध बेचती है, संपत्ति है 100 करोड़ की?

सौ करोड़ की जमीन की मालिक संजू देवी मीणा खेती और पशुपालन कर अपने बच्चों को पाल रही है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके नाम 100 करोड़ की कीमती जमीन कहां है? वह तो बस इतना जानती है कि पति की मौत के बाद कोई उसे हर महीने 5000 रुपए घर खर्च के लिए भेजता था। वह भी अब तीन साल से बंद हो गया है।

दरअसल, संजू देवी के नाम से जयपुर दिल्ली हाइवे पर छह गांवों में इन 64 बेनामी संपत्तियों को खरीदने का यह खेल मुंबई के हीरानंद ग्रुप की 'हेजलनट कंस्ट्रक्शन' कंपनी का था। इन्हें आयकर विभाग ने प्रोविजनल रूप से अटैच कर दिया है। सामने आया कि संजू देवी का पति नारूराम मुंबई मे काम करता था। उसके साथ मुंबई के कुछ लोग आए थे और 2006 में जमीन के इन कागजों पर उससे अंगुठे लगवाए गए थे। *(रा.प., 03.07.19)*

बढ़ रहा है भ्रष्टों की सजा का प्रतिशत

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी शुरू कर दी है। बदली रणनीति से पिछले 10 साल में बड़ा बदलाव आया है। अदालत में होने वाली प्रभावी पैरवी का ही नतीजा है कि पहले एक तिहाई भ्रष्टाचारियों को सजा हो पाती थी अब आधे मामलों में सजा होने लगी है।

एसीबी ने अदालत में पैरवी का तरीका बदला तो इससे जहां कभी 33 प्रतिशत मामलों में ही सजा हो पाती थी, वहीं अब 53 प्रतिशत मामलों में सजा होने लगी है। एसीबी के विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान के अनुसार एसीबी में आरोपी सरकारी विभाग के कर्मचारी व अधिकारी होते हैं।

अधिकारी जितना बड़ा होगा, उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाना उतना ही मुश्किल होता है। फिर भी तकनीकी साक्ष्यों के साथ प्रभावी पैरवी के कारण आरोपियों को सजा हो रही है। सजा का प्रतिशत और बढ़े इसके लिए सुनवाई भी समय पर होना जरूरी है। *(रा.प., 12.08.19)*

अभियोजन स्वीकृति देने में लेटलतीफी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक के बाद एक ट्रैप और आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में कार्रवाई कर रही है। लेकिन विभागों में अभियोजन स्वीकृति देने में लेटलतीफी के चलते भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कानून के शिकंजे से बच रहे हैं। हालात यह है कि एक जुलाई 2019 तक 208 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने से लंबित पड़े हैं।

इनमें सबसे अधिक कार्मिक विभाग में लंबित हैं। वहीं गौर करने वाली बात है कि पुलिस विभाग से ही चुने गए अधिकारी और कर्मचारी एसीबी में लगाए जाते हैं, लेकिन एसीबी सीधे मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम करती है। इसके चलते एसीबी को पुलिस विभाग से भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मियों की अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। *(रा.प., 11.08.19)*

भ्रष्टाचारीयों को फील्ड पोस्टिंग

जनता से जुड़े और राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में भ्रष्टाचार के मामले आए दिन पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आरोपी अधिकारी इतने प्रभावशील है कि मामलों का निस्तारण होने से पहले ही फिर से फील्ड में अच्छी पोस्टिंग पा रहे हैं। परिवहन विभाग इसका ताजा उदाहरण है, जहां पिछले वर्षों में 61 अधिकारी भ्रष्टाचार व अन्य गड़बड़ियों में पकड़े गए, उनमें से 55 के खिलाफ एसीबी में मामले लंबित हैं।

इसके बावजूद 31 अधिकारी अहम पदों पर फील्ड में तैनात हैं। इसी प्रकार 5 अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 16 सीसीए की विभागीय कार्रवाई चल रही है। *(रा.प., 07.09.19)*

भ्रष्ट अफसरों को करेंगे रिटायर : गहलोत

प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग, सीएमओ तथा पुलिस के बड़े अफसरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।

जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षकों को ज्यादा अधिकार व जिम्मेदारी दिए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने अवैध बजरी खनन रोकने, उसमें लगी मशीनों को जब्त करने और अवैध बजरी परिवहन को रोकने के निर्देश दिए। *(दै.भा., 05.08.19)*

घूसखोरी में राजस्थान पुलिस प्रदेश में नंबर वन

स्वच्छ और बेदाग छवि के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों के बीच भ्रष्टाचार मुक्त माहौल पैदा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवस्था स्थापित करने वाली पुलिस मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने में लगी है। हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सामने आया है कि प्रदेश में राजस्थान पुलिस के हाथ घूस की रकम से ज्यादा काले हुए हैं। प्रदेश पुलिस वर्ष 2018 (पूरा वर्ष) और एक जनवरी से 28 अगस्त 2019 तक घूस लेने के मामले में नंबर वन पर है। जबकि दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग और तीसरे नंबर पर पंचायत विभाग में तैनात कर्मचारी और अधिकारियों ने घूस लेने में रिकॉर्ड बनाया है।

डीजी आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में एसीबी ने बजरी से अवैध वसूली करने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने कई बड़े घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। काला धन इकट्ठा कर अकूत सम्पत्ति बनाने वाले अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आम जन आज भी थाने जाने से डरता है। कोई भी पुलिसकर्मी किसी को भी थाने ले जाकर पीट देता है। ऐसे में कहा जाता है कि पुलिस पीटती है। इस कारण आमजन को घूस देनी पड़ती है। खुलासा हुआ है कि पुलिस से पीड़ित व्यक्ति ही सबसे ज्यादा एसीबी के पास पहुंचते हैं। एसीबी ने एक के बाद एक कार्रवाई की तो पुलिस विभाग का भ्रष्टतम चेहरा सामने आया। *(दै.न., 02.09.19)*

एसीबी में कोई भी पीड़ित किसी भी घूसखोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। पीड़ित चाहेगा तो पूरी गोपनियता के आधार पर घूसखोर पर कार्रवाई होगी। एसीबी हर घूसखोर के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी।

– आलोक त्रिपाठी, महानिदेशक, एसीबी राजस्थान

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
चित्तौड़गढ़	राजाराम मीणा	थानाधिकारी, भैंसरोड़गढ़ थाना	25,000	दै.न., 10.07.19
जयपुर	छुट्टन लाल शर्मा कैलाश चन्द शर्मा	एसआई, ब्रह्मपुरी थाना, जयपुर दलाल	1,00,000	रा.प. एवं दै.भा., 20.07.19
बीकानेर	महमूद खां	सीओ, नोखा, बीकानेर	50,000	रा.प., 27.07.19
जोधपुर	मूमल बूब जोगेन्द्र सिंह	इंस्पेक्टर, आबकारी विभाग सिपाही, आबकारी विभाग	30,000	रा.प. एवं दै.भा., 30.07.19
अलवर	सुमन मेघवाल राहुल तंवर	महिला पटवारी, महेसरा गांव, टपूकड़ा सुमन मेघवाल का भाई	91,000	रा.प. एवं दै.भा., 31.07.19
भीलवाड़ा	नितिन पारीक	व्यवस्थापक, ग्राम सेवा स. समिति, सिदड़ियावास	25,000	दै.भा. एवं रा.प., 31.07.19
भीलवाड़ा	दिनेश कुमार भांबी	ग्राम विकास अधिकारी, कीड़ीमाल पंचायत, मांडल	50,000	रा.प. एवं दै.भा., 01.08.19
जयपुर	अनुसूइया कुमारी कमल चंद रवि पारीक	स. कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग, झालाना संस्था स. लेखाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, झालाना रिटायर क्लर्क, वाणिज्य कर विभाग, झालाना	1,15,000	रा.प., 03.08.19
जयपुर	मनोज कुमार	स. प्रशासनिक अधिकारी, नगरपालिका कोटपुतली	27,000	दै.भा., 06.08.19
चूरू	हरजिंदर सिंह	थानाधिकारी, रतनगढ़, चूरू	45,000	रा.प. एवं दै.न., 10.08.19
जयपुर	रती राम तारा चंद	एएसआई, मानसरोवर थाना, जयपुर दलाल	75,000	रा.प. एवं दै.भा., 30.08.19
उदयपुर	भानु कुमार	कनिष्ठ लिपिक, एसडीएम कार्यालय, झाड़ोल	25,000	दै.भा., 03.09.19
जयपुर	बंशीधर कुमावत विकास डांगी, ओम सिंह	जॉइंट सेक्रेट्री, खान विभाग दलाल	4,00,000 3,00,000	रा.प. एवं दै.भा., 05.09.19
जयपुर	किशन चंद सिंधी	सहायक लेखाधिकारी, एजी ऑफिस, जयपुर	1,10,000	रा.प., 24.09.19
जालौर	जगदीश प्रसाद वर्मा	स. अभियंता, नर्बदा नहर परियोजना (जल संसाधन)	1,00,000	रा.प., 24.09.19

किसानों की होगी दोगुनी आय

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कृषि और संबंधित कार्यों पर सरकार इस वित्त वर्ष में 1.51 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह पिछले बजट की तुलना में दो गुना से भी ज्यादा है। कृषि, सिंचाई, फसल बीमा, मूल्य समर्थन समेत कई योजनाओं में बजट आवंटन बढ़ाया गया है। नए मॉडल के जरिए जीरो बजट फॉर्मिंग पर पूरा जोर रहेगा।

किसानों की पेंशन के लिए 900 करोड़, पीएम-आशा योजना के लिए 1500 करोड़ और किसान सम्मान के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। सिंचाई योजना में 253 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर 9680 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे, जिससे खेती-किसानी कॉरपोरेट तरीके से हो सकेगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रदेश के बजट में 1000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष बनाने और उससे किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने की घोषणा की गई है। जीरो बजट नेचुरल फॉर्मिंग पर बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही की 36 ग्राम पंचायतों में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि के लिए बहुउपयोगी व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। बजट में 10 लाख किसानों को फसली ऋण वितरण के लिए 16 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 700 भंडारों का निर्माण कराया जाएगा।

(रा.प. दै.भा., दै.न., 06.07.19, 11.07.19)

अब जन सूचना पोर्टल पर सब मौजूद

आरटीआई के तहत जनता को सूचना नहीं मांगनी पड़े, इसके लिए सिविल सोसायटी व आईटी विभाग की दो साल की मेहनत के बाद डिजिटल पोर्टल 'जन सूचना' बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में देश का मॉडल स्टेट बने।

उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पब्लिक डिलीवरी वाले सभी विभागों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। शुरुआत 13 विभागों और 23 योजनाओं से की गई है। इनमें राशन, निःशुल्क दवा योजना, कर्ज माफी, अल्पकालीन ऋण, शाला दर्पण, खनन आवंटन से जुड़ी जानकारी हर लाभार्थी ले सकेगा। उन्होंने कहा कि आरटीआई में यह प्रावधान है कि सरकारें स्वयं ही आमजन को अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराए, ताकि लोगों को इस अधिकार के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़े।

(दै.भा., 14.09.19)

लुभा रही है 'किसान सम्मान योजना'

प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लुभा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक लाभ लेने के इच्छुक किसानों की संख्या राज्य के कर्जदार किसानों से भी ज्यादा है। इस योजना के तहत अब तक आए आवेदनों से यह सच सामने आया है। इस योजना में प्रदेश के 60 लाख 78 हजार किसान अब तक आवेदन कर चुके हैं और यह क्रम अभी जारी है।

इस योजना की पात्रता के नियम काफी सरल है। योजना के तहत किसानों को एक साल में 6 हजार रुपए देना तय है। यह सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में मिलेगी। प्रदेश में जिसके नाम की कृषि भूमि है वह इस योजना का पात्र है। पहले लघु और सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद यह बंधन भी हटा दिया है।

(रा.प., 30.08.19)

जनजातियों में पहुंचे विकास का लाभ

राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजाति विकास विभाग को निर्देश दिया है कि जनजाति क्षेत्रों में विकास के लिए आवंटित बजट की 75 प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह तक उपयोग में आ जानी चाहिए।

कार्यों की गुणवत्ता और विकास का लाभ जनजाति क्षेत्रों को भरपूर मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि बजट का समुचित उपयोग समय पर किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं।

(रा.दू. 17.09.19)

धारा 370 हटाने से लोग खुश : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर की मुक्ति को जरूरी बताते हुए इस पर आपत्ति करने वालों से देशहित को सर्वोपरि रखने और देश की भावनाओं का आदर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सभी को नए भारत, नए जम्मू-कश्मीर और नए लद्दाख के निर्माण में भागीदारी करने का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि धरती के स्वर्ग पर अब नए युग की शुरुआत होगी। उन्हे विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद और आतंकवाद को परास्त कर नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद व भ्रष्टाचार को समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए वहां तेजी से विकास योजनाएं लागू करने की है।

(दै.न., 09.08.19)

लोकसभा में हुआ अब तक का सबसे ज्यादा कामकाज

मोदी सरकार दूसरी पारी में संसद में कामकाज का नया रिकॉर्ड बना रही है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में सरकार अब तक 30 विधेयक पास करा चुकी है। सरकार का दावा है कि 67 साल बाद लोकसभा में इतना कामकाज हुआ है। इससे पहले 1952 में 64 दिन चले सत्र में 27 विधेयक पास हुए थे। लोक सभा एवं राज्य सभा में भी मोदी सरकार 25 विधेयक पेश कर चुकी है। संसद में मौजूदा सत्र में 37 बिल पेश किए जा चुके हैं।

इतनी संख्या में बिल पास होने और देर रात तक चल रही संसद कार्यवाही को देखते हुए इस बजट सत्र को अब तक का सबसे सफल लोकसभा सत्रों में से एक माना जा रहा है। इस सत्र में अब तक लोकसभा की कामकाज करने की दर (प्रोडक्टिविटी) 132 प्रतिशत रही, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मानी जा रही है।

(दै.भा., 04.08.19)

स्मार्ट मीटर से कसेगा चोरों पर शिकंजा

अब बिजली मीटरों से गड़बड़ी करना आसान नहीं होगा। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। स्मार्ट मीटर लगने से विभाग के कर्मचारियों को घर-घर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कर्मचारी कन्ट्रोल रूम में बैठे-बैठे ऑनलाइन रिडिंग ले सकेंगे।

मीटर से छेड़छाड़ की जानकारी भी ऑनलाइन ले सकेंगे। इससे बिजली चोरी का पता लगाया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर पहले वहां लगाए जाएंगे जहां लाइन लॉस सबसे ज्यादा है। ऑनलाइन फाल्ट की जानकारी मिल जाएगी। विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर फाल्ट को दुरुस्त कर देगी। *(न.नु., 30.08.19)*

भारी पड़ रही है अफसरों की लापरवाही

बिजली का उपभोग करने वाली कई सरकारी एजेंसियों द्वारा बिजली का बिल नहीं चुकाना आमजन पर भारी पड़ रहा है। अभी राज्य में 325 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली शुल्क सरकारी एजेंसियों में बकाया है। यह बकाया राशि विद्युत टैरिफ का हिस्सा बन रही है। अगले माह टैरिफ याचिका सुनवाई के दौरान लोग बकाया रोकड़ का मामला भी उठाएंगे। क्योंकि, सब्सिडी के पेटे ही राज्य सरकार को करोड़ों रुपए चुकाने हैं।

जलदाय विभाग पर अब भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। उदाहरण के लिए जलदाय विभाग जनता को पेयजल सप्लाई कर रहा है, इसलिए डिस्कॉम नहीं चाहता कि कनेक्शन काटने की स्थिति में लोगों को परेशानी हो। डिस्कॉम ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। *(रा.प., 20.09.19)*

बंजर भूमि से दमकेगा उजाला

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसानों की अनुपजाऊ भूमि की तलाश शुरू हो गई है। ऊर्जा विभाग ने तीनों डिस्कॉम प्रशासन को ऐसे जीएसएस चिन्हित करने के लिए कहा है, जहां 2 मेगावॉट से अधिक लोड हो और किसानों की अनुपयोगी भूमि भी उपलब्ध हो।

केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पैनल लगाने की छूट दी जाएगी। इसमें लागत की 30 प्रतिशत राशि केंद्र व 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। कृषि उपभोक्ताओं को लोन के रूप में 30 प्रतिशत रकम नाबार्ड फाईनेंस करेगा, जबकि बाकी 10 फीसदी राशि नकद देनी होगी। अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने पर किसान बची हुई बिजली बेच सकेगा। *(रा.प., 17.07.19)*

सौर-पवन ऊर्जा नीति का प्रारूप तैयार

सरकार ने प्रदेश की नई सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा नीति-2019 का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस नई नीति के जरिए सरकार ने अगले पांच सालों में 25 हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नीति में बड़े सौर ऊर्जा पार्क विकसित करना, भवनों की छतों पर छोटे संयंत्र लगा कर उन्हें ग्रिड से जोड़ने व उससे उत्पादित होने वाली ऊर्जा की मीटरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने पर फोकस किया गया है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया राजस्थान की भोगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहां सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए सरकार इन सेक्टरों में अधिक से अधिक निवेश आमंत्रित कर रही है। *(दै.भा., 02.09.19)*

बिजली कंपनियों पर लगेगी पेनल्टी

सरकार बिजली क्षेत्र में दूसरे सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। यह जानकारी देते हुए बिजली मंत्री आर.के.सिंह ने कहा कि हम बिजली क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के तहत उपभोक्ताओं को अधिकार दे रहे हैं।

ग्राहकों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलने पर वितरण कंपनियों को उन्हें जुमार्ना भरना होगा। इतना ही नहीं ट्रांसफॉर्मर या किसी अन्य स्थानीय गड़बड़ी के निर्धारित समय सीमा में ठीक नहीं होने पर भी ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। यह मंत्रीमंडल के पास है जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बिजली दरों को वाजिब स्तर पर बनाए रखने, क्रॉस सब्सिडी व्यवस्था पर लगाम लगाने और सब्सिडी का लाभ सीधे ग्राहकों को देने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। *(न.नु., 05.09.19, 06.09.19)*

चोरी व छीजत का भार भी जनता पर

लाखों उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आर्थिक बोझ बढ़ाने के पीछे अफसरों की लापरवाही सामने आई है। इसमें बिजली उत्पादन और वितरण निगम शामिल है। जहां विद्युत उत्पादन की कार्यप्रणाली में खामी के कारण फ्यूल व अन्य खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं वितरण निगम स्तर पर बिजली सप्लाई और बिलिंग में लगातार बढ़ते अंतर के कारण फ्यूल सरचार्ज का ग्राफ बढ़ा है।

जनवरी से मार्च तक डिस्कॉम ने 831.55 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी, लेकिन बिलिंग केवल 574.60 करोड़ यूनिट की ही हुई। यानि, 257 करोड़ यूनिट बिजली की छीजत (चोरी) हो गई। फ्यूल सरचार्ज की दर बढ़ाने के पीछे यह छीजत भी मुख्य वजह बनी और बढ़ी हुई दर का बोझ जनता पर डाल दिया गया, जो 55 पैसा प्रति यूनिट है। बिजली छीजत कम होती तो बिजली कम खरीदनी पड़ती और फ्यूल सरचार्ज की राशि भी कम होती। *(रा.प., 02.07.19)*

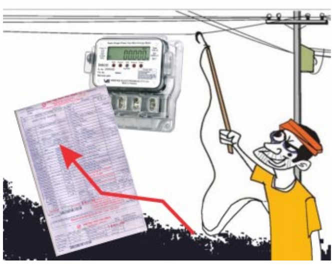

बिल में करंट दौड़ाने की टैरिफ याचिका दायर

राज्य सरकार ने बिजली के बिल में बढ़ोतरी करने की टैरिफ याचिका को राज्य विद्युत विनियामक आयोग को सौंप दी है। इसमें उद्योगों को राहत देने का प्रस्ताव है तो वहीं आमजन के बिल में करंट दौड़ाना तय है। हालांकि बीपीएल व लघु उपभोक्ताओं पर भार डालने का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत दर (टैरिफ) में 10 से 12 फीसदी तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा फिक्स चार्ज भी बढ़ेगा। कृषि के लिए भी बिजली करीब 25 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है। इन पर बढ़ा हुआ भार सरकार सब्सिडी देकर उठाएगी या इसे उपभोक्ताओं से वसूलेगी, यह याचिका पर सुनवाई के बाद ही तय होगा। टैरिफ याचिका में करीब 80 लाख उपभोक्ताओं पर सीधा भार डालने की तैयारी है। याचिका में घाटे की स्थिति बताई है। *(रा.प., 08.08.19)*

जन आंदोलन बने जल संरक्षण : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पानी की कमी को देखते हुए देशवासियों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान करते हुए कहा है कि इसके लिए पारंपरिक तौर-तरीकों पर जोर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे स्वच्छता अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है, वैसे ही जल संरक्षण के लिए भी जन आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें। उन्होंने कहा कि मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, पानी पारस का रूप है। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए सभी देशवासी अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान की शुरुआत करें। *(दै.न., 01.07.19)*

पानी बचाने के लिए सख्त कानून

भूजल को बचाने के लिए राजस्थान वाटर (कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट नाम से ड्राफ्ट बनाया गया है। इसमें पानी के संरक्षण व इस्तेमाल के लिए सख्त कानून है। जलदाय मंत्री बुलाकीदास कल्ला ने बताया कि इस पर जलदाय मंत्रियों की दिल्ली में आयोजित बैठक में मंथन होगा।

उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश में भूजल दोहन रोकने, उसके संरक्षण के लिए किसी तरह का कानून नहीं है। राज्य में औसतन 1.5 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर बारिश होती है। गंभीर यह है कि एक लाख मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 33 जिलों में से 26 जिले डार्कजोन में हैं। इस बार बारिश अच्छी हुई है इसलिए अब पानी को सहेजने व संरक्षण पर काम होगा। प्रस्तावित एक्ट में पेनल्टी व सजा का प्रावधान भी किया गया है और जनता की जिम्मेदारी भी तय की गई है। *(रा.प., 02.07.19, 25.08.19)*

स्वच्छ भारत की तर्ज पर जलनिधि कोष

नवनिर्मित जलशक्ति मंत्रालय मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' के तहत 2024 तक हर ग्रामीण भारतीय के घर तक पाइप के जरिए प्रति व्यक्ति रोजाना 55 लीटर पानी पहुंचाने की तैयारी में लगा है। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के 'स्वच्छ भारत कोष' की तर्ज पर 'राष्ट्रीय जल जीवन कोष' बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन का ऐलान करते हुए कहा कि इस पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने की योजना है। मंत्रालय के अधिकारी 'नाल से जल' (नलों से पानी पहुंचाना) के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे रहे हैं, जो घरों में पीने योग्य पानी मुहैया कराने पर जोर देता है। *(रा.प., 30.08.19, 05.09.19)*

जल संकट की चपेट में भारत

एक तरफ बेतहाशा बारिश दूसरे ओर पेयजल संकट। जलवायु परिवर्तन यही है। करीब 200 नदियों वाला भारत बेहद गंभीर जल संकट की चपेट में है। भारत दुनिया के उन 17 देशों में शामिल हो गया है जो बेहद जल संकट का सामना कर रहे हैं।

विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) के एक्वाडक्ट वॉटर रिस्क एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक 17 देश पानी खत्म होने की स्थितियों के करीब है। जल संकट वाले देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर पहुंच गया है। संगठन ने 189 देशों में जल संकट, सूखे और बाढ़ की आशंका पर रैंकिंग जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 1990 से 2014 के बीच प्रति वर्ष 8 सेमी की दर से भूजल में गिरावट आई है। *(रा.प., 08.08.19)*

भूजल संकट के कगार पर राजस्थान

राजस्थान भूजल संकट के कगार पर है। भूजल के 295 ब्लॉक में से 184 अतिदोहित श्रेणी में आ चुके हैं। आधे से ज्यादा राज्य में जमीनी पानी कभी भी समाप्त हो सकता है।

भूजल मंत्री बुलाकीदास कल्ला ने राज्य विधानसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में दो-तिहाई हिस्सा मरूस्थल है। औसत वर्षा अत्यधिक कम होने के कारण वर्षा जल की एक-एक बूंद को बचाना और पानी का मितव्ययता से उपयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विधायकों ने चिंता जाहिर करते हुए इस संकट को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिए। *(न.नु., 29.07.19)*

ऑस्ट्रेलिया तकनीक का होगा उपयोग

पानी को शुद्ध करने के लिए अब किसी तरह के केमिकल की जरूरत नहीं रहेगी। बल्कि, पानी से ही क्लोरीन उत्पन्न होगा और उसी के जरिए पानी शुद्ध (बैक्टेरिया मुक्त) हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की इस हाइड्रो-डिस तकनीक को राजस्थान में उपयोग करने के लिए जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है।

इस तकनीक में पेयजल लाइन के बीच में ही टाइटेनियम की ट्यूब जोड़ देते हैं। इस ट्यूब में विशेष प्रकार का लेप लगा हुआ है। पानी को इस ट्यूब से गुजारा जाता है। इससे पानी फिल्टर होकर निकलता है। पहले फेज की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है और अब दूसरी जांच रिपोर्ट माशेलकर कमेटी के पास पहुंच गई है। कमेटी की हरी झंडी के बाद इस तकनीक को राजस्थान में पूरी तरह लागू करने की राह खुल जाएगी। *(रा.प., 08.09.19)*

प्रदेश में आएगा पाकिस्तान जा रहा पानी

पाकिस्तान में बह रहे पानी में से 6 हजार क्यूसेक पानी राजस्थान में लाने का काम जल्द तेज होगा। करीब 1900 करोड़ रुपए से फीडर सुधारने का काम होगा, जिसके लिए पंजाब सरकार ने निविदा जारी कर दी है। इसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राजस्थान सरकार वहन करेगी। सरहिन्द फीडर सहित 3 फीडरों को सुधारा जाएगा। ये फीडर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गुजर रहे हैं।

यह काम पूरा होने के बाद राजस्थान को छह हजार क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिलने लगेगा। इंदिरा गांधी नहर के जरिए यहां 18500 क्यूसेक पानी लाया जा सकता है। लेकिन फीडरों की स्थिति सही नहीं होने के कारण करीब 12 हजार क्यूसेक पानी ही आ पा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें 3 से 4 वर्ष तक का समय लगेगा। *(रा.प., 13.07.19)*

महिला लीडरशिप को दिया प्रोत्साहन

आम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला लीडरशिप को प्रोत्साहित किया है। स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इसके साथ ही जन-धन खाते से 5000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट देने की अनुमति भी दी गई है। इससे महिलाएं लघु उद्योग या कोई व्यवसाय शुरू कर अर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी। महिलाओं की इस भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुनहरी होगी। 'नारी तू नारायणी' योजना शुरू होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव देगी। महिला केंद्रित पॉलिसी के तहत महिला लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास होगा।

प्रदेश के बजट में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए की प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी शक्ति योजना की घोषणा की गई है। इससे महिलाओं को उद्यम स्थापना, आधुनिक अनुसंधान के लिए सहायता तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जा सकेगी। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यकों के बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21 हजार रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। *(रा.प. दै.भा., दै.न., 06.07.19, 11.07.19)*

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' में श्रेष्ठ

राजस्थान को लगातार तीसरी बार 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ओ' योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 'श्रेष्ठ राज्य' श्रेणी से पुरस्कृत किया गया है।

राज्य की ओर से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह मे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस मौके पर ईरानी ने राजस्थान द्वारा इस योजना में किए गए कार्यों की सराहना की।

इसके साथ ही इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 'सेक्स रेशो एट बर्थ' बढ़ोतरी वाले देश के 10 जिलों की श्रेणी में जोधपुर जिले को तथा 'अवेयरनेस जनरेशन एंड आउटरीच एक्टीविटीज' श्रेणी के लिए श्रेष्ठ 10 जिलों की श्रेणी में नागौर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(दै.भा. एवं रा.प., 07.09.19)

आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करेगी सरकार

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में प्री-प्राइमरी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करेगी। प्रदेश के 38 हजार इंटीग्रेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष सुविधाओं के तहत कमरे तैयार कराने के साथ ही वहां बच्चों के लिए वॉल पेंटिंग लगाई जाएगी।

डोटासरा ने विभाग की विशेष समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम का भी लोकार्पण किया। राज्य के सभी मॉडल स्कूलों में प्री-प्राइमरी स्वीकृत हो गई है। उन्होंने अधिकारियों को इन्हें सशक्त किए जाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। *(रा-.प., 14.09.19)*

महिला विकास के लिए बनाई योजनाएं

प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी के नाम से सात योजनाएं लेकर आ रही है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। यदि सबकुछ ठीक रहा तो सभी योजनाएं जल्द ही लागू कर दी जाएगी। इन सभी योजनाओं पर सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन योजनाओं से पूरा फायदा महिलाओं को मिलेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए इन योजनाओं के तहत उद्यमीय प्रोत्साहन, कौशल विकास एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। *(दै.न., 07.08.19)*

महिलाओं की विजय 'तीन तलाक बिल'

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल के पारित होने पर केंद्र सरकार के प्रयासों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें गरिमापूर्ण सम्मान मिलेगा।

प्रदेश के विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि राज्यसभा में महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन और उनके सम्मान से जुड़े बिल के पारित होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए अनवरत प्रयासों से देश के इतिहास में तीन तलाक का दंश झेल रही महिलाओं के लिए यह दिन विजय के दिन के रूप में दर्ज हुआ है। *(रा.प., 31.09.19)*

फैमिली प्लानिंग का जिम्मा महिलाओं पर?

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम व योजनाओं के बाद भी महिलाओं की तुलना में पुरुष नसबंदी के आंकड़े शर्मनाक हैं। सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि देने के बावजूद परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी न के बराबर है। आंकड़ों के मुताबिक नसबंदी कराने वाले पुरुष महज एक से दो फीसदी है।

परिवार नियोजन में 98 फीसदी महिलाओं का हाथ है। पति को भी अपनी पत्नी का ही ऑपरेशन कराने में ज्यादा विश्वास है। पुरुषों को नसबंदी के लिए आकर्षित करने के लिए कुछ जिलों में स्मार्टफोन, फ्रीज, एलईडी जैसे कई उपहार देने के बाद भी आंकड़े नहीं सुधर रहे। पुरुष नसबंदी में पिछड़ने का प्रमुख कारण कमजोरी आने और वैवाहिक जीवन प्रभावित होने जैसे मिथक हैं। *(दै.भा., 19.07.19)*

सड़क सुरक्षा

अब भारी पड़ सकती है ट्रैफिक नियमों की अनदेखी

सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद मोदी सरकार ने एक सितंबर से इसे लागू कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि विधेयक के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू कर दिया गया है। अगर किसी ने नियमों की अनदेखी की, तो उसे ज्यादा जुर्माना देना होगा। क्योंकि, इसमें विभिन्न चालान की राशि को बढ़ा दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि नए नियमों से सड़क हादसों में कमी आएगी।

यातायात के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना	
शराब पीकर गाड़ी चलाना	*10,000 रु.*
बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाना	*5,000 रु.*
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	*5,000 रु.*
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर	*1,000 रु.*
सीमा से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर	*1,000 से 2,000 रु. तक*
गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर	*5,000 रु.*
दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर	*1,000 रु.*
लाल लाइट क्रॉस करने पर	*500 रु.*

गडकरी ने कहा कि सरकार ने अगले पांच साल में सड़क हादसों में पचास फीसदी कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार 14 हजार करोड़ रुपए का मेगा प्लान तैयार कर रही है। जुर्माना बढ़ाने का फैसला काफी समझ-बूझकर और विभिन्न पक्षों से राय लेकर लागू किया गया है। इसके कुछ प्रोविजन पर राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से इन नियमों में बदलाव कर सकते हैं और कुछ मामलों में जुर्माने की राशि भी एक सीमा तक कम या ज्यादा कर सकते हैं।

(दै.न., 22.08.19)

जन स्वास्थ्य

आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ कवर

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष बजट में 19 फीसदी का इजाफा कर जन स्वास्थ्य को खास अहमियत दी है। स्वास्थ्य का बजट अब 62 हजार 659 करोड़ रुपए हो गया है। आयुष्मान योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योजना के तहत 10.74 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 34.97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसके तहत 1.5 लाख सब-सेंटर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 2022 तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में बदला जाएगा। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन स्वास्थ्य के लिए बजट में 12750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें अब किडनी, हार्ट और कैंसर की 104 नई दवाइयों को शामिल किया गया है। कई बीमारियों की जांचें भी मुफ्त की गई हैं। गली-मोहल्लों में 200 नए जनता क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इन्हें निःशुल्क दवा योजना से जोड़ा जाएगा।

(रा.प., दै.भा., दै.न., 06.07.19, 11.07.19)

पर्यावरण

सिंगल यूज प्लास्टिक को कहे अलविदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि क्षरण मसले पर दुनिया में कई कदम उठाने को तैयार है। भारत सिंगल यूज (एक बार इस्तेमाल कर फेंकने वाली) प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने की ओर बढ़ चुका है और अगले कुछ वर्षों में इससे पूरी तरह छुटकारा पा लेगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया भी इसे अलविदा कर दे।

प्रधानमंत्री ने यह बात नोएडा के एक्सपो में आयोजित मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन के सदस्य देशों (कॉप-14) की बैठक में कही। उन्होंने ऐलान किया कि भारत 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाएगा।

(रा.प., 10.09.19)

राजस्थान को हरा-भरा बनाएं : गहलोत

हमारी इच्छा राजस्थान को हरा-भरा बनाने की है। इसके लिए वन विभाग को बड़े स्तर पर काम करने होंगे। यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 70वें वन महोत्सव में कही। उन्होंने पर्यावरण पर चिंता जताते हुए कहा कि 20 साल पहले भी पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर मैंने हरित राजस्थान की बात की थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों का जितना ऐरिया होना चाहिए, उसका आधा भी नहीं है। पेड़ लगाना एक बात है, लेकिन उनको बचाकर बड़ा करना बड़ी बात है। वन होंगे तो ही अच्छी बरसात होगी। फसलें अच्छी होंगी जिससे खुशहाली आएगी। इस अवसर पर उन्होंने इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया और बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू किया।

(दै.भा., 07.09.19)

वित्तीय सेवाएं

पिछले एक साल में बढ़ी बैंकों से धोखाधड़ी

देश में पिछले एक साल में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जबकि धोखाधड़ी की राशि 73.8 फीसदी बढ़कर 71,542.93 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। धोखाधड़ी के कुल 6,801 मामले सामने आए हैं। रिजर्व बैंक ने यह जानकारी अपनी सालाना रिपोर्ट में दी है।

रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि 2020 के लिए विकास दर 6.9 प्रतिशत तक रह सकती है। पहली छमाही में 5.8 से 6.6 प्रतिशत तक और दूसरी छमाही के दौरान 7.3 से 7.5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।

(दै.भा., 30.08.19)

उपभोक्ता फैसले

समय पर नहीं पहुंचा कन्यादान, डाक विभाग को देना होगा हर्जाना

जयपुर स्थित मुक्तानंद नगर, गोपालपुरा बाइपास निवासी एस.पी. गुप्ता ने राजस्थान सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एवं जयपुर देहात मंडल डाकघर अधीक्षक के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर (प्रथम) में परिवाद दायर किया। परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि 24 फरवरी 2014 को उनके सहयोगी अनिल कुमार मिश्रा की पुत्री का विवाह बांदीकुई में होना था। शादी में खुद न जाने के कारण कन्यादान के लिए 20 फरवरी को उन्होंने दुर्गापुरा स्थित डाकघर से 101 रुपए का ई-मनिआर्डर भेजा था। यह मनिआर्डर शादी के 21 दिन बाद 18 मार्च को पहुंचा। जबकि कन्यादान शादी से पूर्व पहुंचना चाहिए था।

मामले की सुनवाई पर डाक विभाग की ओर से दलील दी गई कि 20 फरवरी से 17 मार्च तक बांदीकुई सर्वर में तकनीकी खराबी चल रही थी, ऐसे में उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन विभाग की ओर से सर्वर में क्या खराबी हुई इसके कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए। मंच ने डाक विभाग की ओर से दी गई इस दलील को सही नहीं ठहराया और समय पर मनिआर्डर नहीं पहुंचाने को सेवा में कमी का दोषी माना। उपभोक्ता मंच ने डाक विभाग को आदेश दिया कि वह एस.पी गुप्ता को हुए मानसिक संताप के बदले 3000 रुपए और परिवाद व्यय के रूप में 3000 रुपए, यानी कुल राशि 6000 रुपए अदा करे। *(रा.प., 08.08.19)*

आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया 33 लाख रुपए का हर्जाना

जयपुर निवासी दशरथ सिंह ने आईसीआईसीआई बैंक की सी-स्कीम शाखा एवं बैंक कर्मचारी नितिन कुमार के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग की बैंच-2 में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया गया कि उन्होंने 16 मार्च 2011 को बैंक में अपने खाते में 27 लाख रुपए जमा कराए थे। सेल्स मैनेजर नितिन कुमार ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके नाम से दूसरा खाता खुलवाया और उनके खाते से 28 लाख रुपए निकाल लिए। उन्होंने बैंक में इसकी शिकायत की और जमा राशि लौटाने के लिए कहा। लेकिन बैंक द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमा राशि का बैंक कर्मचारी द्वारा गबन करने के कारण वह अपने व्यवसाय में इस राशि का उपयोग नहीं कर पाए। इससे उन्हें व्यवसाय में काफी नुकसान हुआ। उन्होंने परिवाद में आयोग से प्रार्थना की कि उन्हें 28 लाख रुपए मय ब्याज व हर्जाने सहित दिलवाए जाएं।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक और कर्मचारी नितिन कुमार को फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी कर परिवादी की जमा राशि का गबन करने का दोषी माना। उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक और दोषी कर्मचारी पर 33 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए आदेश दिया कि हर्जाना राशि पर ब्याज भी अदा किया जाए। *(दै.भा., 23.08.19)*

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को मिली मंजूरी

उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने और भ्रामक प्रचार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने वाले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पर राज्यसभा एवं संसद की मुहर लग गई है। इसमें उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है। भ्रामक विज्ञापनों पर भारी पेनल्टी और ई-कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रानिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए इसमें सख्त दिशा-निर्देश भी शामिल किए गए हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों से होने वाले नुकसान से बचाना और व्यवस्था को सरल बनाना है। अब कहीं से भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले वह वहीं शिकायत दर्ज करा सकता था, जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है। ई-कॉमर्स की बढ़ती खरीद को देखते हुए यह एक बड़ी राहत है।

नए विधेयक में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में भाग लेने की इजाजत है। इससे उपभोक्ता का पैसा और समय बचेगा। इसमें कंपनी की जवाबदेही भी तय की गई है। मैन्यूफैक्चरिंग में खामी या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो उसे बनाने वाली कंपनी को हर्जाना देना होगा। इस प्रावधान का सबसे ज्यादा असर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होगा। *(न.नु., 31.07.19, 07.08.19)*

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से किया सम्मानित'

कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा 'गुड सेमेरीटन गाईड लाइनः चेलेन्जेज एण्ड वे फॉरवर्ड' विषय पर आधारित राज्य स्तरीय समारोह में दैनिक भास्कर के पत्रकार चेतन कुमार मालवीय को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

चेतन कुमार जोधपुर जिले के बिलाड़ा गांव के निवासी है। उन्होंने वर्ष 2018 के लिए चयनित विषय 'किसानों की स्थिति' विषय पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में अनेक रोचक एवं तार्किक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259
फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)